माननीय न्यायालय □□.□□. □□□□□, □□ □□. □□ □□□□□□

□□□□, □□.

भारत सरकार □□ □□□□, — □□□□□□□□□□□

□□□□

मधु गर्ग □□ **अन्य,** — □□□□□□□□□

L.P.A. संख्या 164, 2006
Crl. W.P. 2003 □□□□□□ 1037

10 □□□□□□, 2008

□□□□ □□ □□□□□□□, ***1950 — अनुच्छेद 226 — अवैध निरोध का आरोप-क्या उच्च न्यायालय को निर्देश देने और जारी करने का अधिकार क्षेत्र है-आयोजित, हाँ-उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट के माध्यम से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए सुरक्षित कर सकता है कि उसे कानूनी हिरासत में रखा गया है या नहीं-प्रतिवादी का पति अब याचिका के निपटारे के समय हिरासत में नहीं है-एक उपयुक्त मंच के समक्ष उपचार लेने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम-अपील की अनुमति, एकल न्यायाधीश द्वारा एक निष्फल मामले में जांच के लिए निर्देश जारी करने के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।***

अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय निस्संदेह एक रिट याचिका को स्वीकार कर सकता है यदि 'कार्रवाई का कारण' या इसका कोई भाग इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले में अधिकारिता ग्रहण करने के लिए दो कारकों पर भरोसा किया है, अर्थात् (i) नरसी राम गर्ग को लुधियाना से उठाया गया है और (ii) मधु गर्ग से तार भी लुधियाना से प्राप्त हुआ था। ये दोनों कारक अप्रासंगिक हैं और किसी भी 'कार्रवाई का कारण' या उसका हिस्सा नहीं हैं। नरसी दास गर्ग की कथित अवैध हिरासत के संबंध में, उनकी पत्नी श्रीमती राकेश गर्ग ने एक अलग तार भेजा था जिसे आपराधिक रिट याचिका के रूप में माना गया था और इस अदालत द्वारा 16 दिसंबर, 2003 को निष्फल होने के रूप में निपटाया गया था। जहाँ तक प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय को भेजे गए तार का संबंध है, वह किसी भी तरह से 'कार्रवाई के कारण' का हिस्सा नहीं है।

(□□□□ 15)

इसके अलावा, यह माना गया कि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता का पति अपने दिल्ली निवास पर था जब उसे डीआरआई अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अवैध हिरासत में लिया गया था। हिरासत में रहते हुए, विनोद गर्ग को कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया और उन्हें केवल दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसी तरह, डीआरआई द्वारा विनोद गर्ग को कथित नोटिस भेजे गए और उन्हें उनके दिल्ली के पते पर भेजा गया। उनके आत्म-निंदात्मक बयान भी केवल दिल्ली में दर्ज किए गए थे। इस प्रकार, विनोद गर्ग की कथित "अवैध हिरासत" से संबंधित सभी घटनाएं केवल दिल्ली में शुरू हुईं और समाप्त हुईं। जबकि प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता कथित बंदी की पत्नी थी, उसके पास 'कार्रवाई का अधिकार' था, लेकिन इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उसे कोई 'कार्रवाई का कारण' नहीं दिया गया था।

(□□□□ 18)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह न्यायालय रिट याचिका को भी स्वीकार कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उचित निर्देश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट का उपयोग किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष सबसे अधिक बार लाने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्ष को कैद या हिरासत में रखना अवैध नहीं है। इस प्रकार, इसका तात्पर्य है कि जब अवैध निरोध की शिकायत होती है, तो उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के माध्यम से यह जांच कर सकता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वैध हिरासत में रखा गया है या नहीं। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का पति उस समय अभिरक्षा में नहीं था जब याचिका 25 अक्टूबर, 2005 को निपटारे के लिए आई थी और इसे एक तरह से निष्फल कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में, उपयुक्त मार्ग यह हो सकता था कि कथित बंदी या रिट याचिकाकर्ता को एक उपयुक्त मंच के समक्ष 'मुआवजा' या किसी अन्य घोषणात्मक राहत जैसे उपाय की मांग करने की स्वतंत्रता दी जा सकती थी ताकि किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह न हो।

(□□□□ 20)

अपीलार्थियों के अधिवक्ता सतीश अग्रवाल और कमल सहगल के साथ भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मोहन प्रसारन।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए पवन गिरधर अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा

अमोल रतन सिंह उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब

सूर्या कांत, □□.

(1) यह आदेश 2006 की एलपीए संख्या 164,165 और 171 का निपटारा करेगा क्योंकि इन अपीलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं जिन्हें भारत संघ और इसके संयुक्त निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय, लुधियाना द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जबकि 2006 की एल. पी. ए. संख्या 164 इस न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा 2003 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1037 में पारित दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, 2006 की एल. पी. ए. संख्या 165 दिनांक 29 मई, 2006 के आदेश पर प्रश्न उठाती है, जिसमें विद्वत एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी संख्या 2 पर 10,000 रुपये का व्यय अधिरोपित किया है। 2006 की एल. पी. ए. संख्या 171 में भी विद्वत एकल न्यायाधीश के 29 मई, 2006 के उसी आदेश का इस हद तक उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लुधियाना की रिपोर्ट के विरुद्ध राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 7 फरवरी, 2006 को दायर आपत्तियों पर विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, तथ्य 2006 के एल. पी. ए. संख्या 164 से लिए गए हैं।

(2) लुधियाना की निवासी श्रीमती मधु गर्ग ने इस अदालत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक तार भेजा, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पति-विनोद गर्ग, जो दिल्ली के रूप नगर में उनके आवास पर थे और 11 A.M तक टेलीफोन पर उनके संपर्क में थे, को राजस्व खुफिया कर्मचारी निदेशालय, दिल्ली द्वारा शनिवार, 23 अगस्त, 2003 को गिरफ्तार किया गया था। तब से उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका है। इसलिए उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करते हुए एक आपराधिक रिट याचिका दायर की, जिसके द्वारा (i) भारत संघ; (ii) संयुक्त निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय (आरयू) लुधियाना और (iii) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लुधियाना को नोटिस जारी किया गया था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि लुधियाना निवासी श्रीमती राकेश गर्ग से एक अन्य तार प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पति-नरसी दास गर्ग (विनोद गर्ग के भाई) को भी राजस्व खुफिया निदेशालय, लुधियाना (इसके बाद डीआरआई के रूप में संदर्भित) के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया था इस रिट को 2003 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1032 के रूप में माना गया था|

जबकि 2003 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1032 (श्रीमती राकेश गर्ग बनाम पंजाब राज्य और अन्य) का निपटारा 16 दिसंबर, 2003 को इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद किया गया था कि याचिकाकर्ता के पति का न तो अपहरण किया गया था और न ही उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था। 2003 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1037 लंबित रही क्योंकि 12 जनवरी, 2005 को ही पंजाब राज्य के विद्वान वकील ने एक बयान दिया कि पंजाब पुलिस के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था और यह मामला दिल्ली में डीआरआई स्टाफ से संबंधित था। तदनुसार डीआरआई, दिल्ली और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद डीआरआई, दिल्ली और चंडीगढ़ में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल को 22 मार्च, 2005 को नए नोटिस जारी किए गए। 11 अगस्त, 2005 को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने विनोद गर्ग नाम के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। इस अदालत ने यह देखने के बाद कि कथित विनोद गर्ग को डीआरआई द्वारा गिरफ्तार किया गया होगा, जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। इस बीच, प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता ने एक विस्तृत आपराधिक विविध आवेदन सं. 2005 का 379 कुछ निर्देशों की मांग करता है, हालांकि, डीआरआई की ओर से मुख्य याचिका के लिए कोई जवाबी-हलफनामा दायर नहीं किया गया था।

(4) 25 अक्टूबर, 2005 को, एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए एसएसपी, लुधियाना को अवैध हिरासत के मामले की जांच करने और तीन महीने की अवधि के भीतर इस अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, यह देखने के बाद कि डीआरआई, दिल्ली ने कई स्थगनों के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया और प्रासंगिक रिकॉर्ड से पता चला कि विनोद गर्ग और उनके भाई नरसी दास गर्ग 23 अगस्त से 25 अगस्त, 2003 तक अवैध हिरासत में रहे थे।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक विविध आवेदन में आरोप लगाया कि उसके पति को 23,24 और 25 अगस्त, 2003 को डीआरआई, दिल्ली के अधिकारियों द्वारा अवैध हिरासत में रखा गया था और बाद में दिखाया गया था कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 और 135 के तहत 25 अगस्त, 2003 को गिरफ्तार किया गया था। उसने

आगे आरोप लगाया कि उसकी 'अवैध हिरासत' की अवधि के दौरान, उसके पति पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज एक आत्म-अपमानजनक बयान देने का आरोप है, जिसे उसने 26 अगस्त, 2003 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष वापस ले लिया था। उन्होंने आगे अपने पति के भाई नरसी दास गर्ग की अवैध हिरासत और नरसी दास गर्ग की पत्नी श्रीमती राकेश गर्ग द्वारा भेजे गए तार के बारे में बताया, जिसे अलग से 2003 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1032 माना गया था। प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने डीआरआई, दिल्ली के अधिकारियों की लॉकरों, एफडीआर आदि की जब्ती के संबंध में कथित अवैध कार्रवाई का विस्तार से उल्लेख किया। और उस पृष्ठभूमि में, "डीआरआई अधिकारियों के हाथों उसके पति की अवैध हिरासत से संबंधित" जांच के लिए एक निर्देश की मांग की।

(6) ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के आदेश के बारे में तब पता चला जब उसके अनुपालन में एसएसपी, लुधियाना ने 13 दिसंबर, 2005 को संयुक्त निदेशक, डीआरआई, लुधियाना को एक पत्र लिखा। अपीलार्थियों ने तदनुसार 25 अक्टूबर, 2005 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध करते हुए 2006 की आपराधिक विविध संख्या 20 दायर की। यह दलील देने के अलावा कि उन्हें कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए मामले में पेश होने के लिए किसी वकील को नहीं लगाया जा सकता था, यह समझाया गया कि 23 अगस्त, 2003 को विनोद गर्ग के विभिन्न व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई थी, लेकिन वह उनमें से किसी में भी मौजूद नहीं पाए गए। हालांकि, उक्त विनोद गर्ग ने 23 अगस्त, 2003 की शाम को डीआरआई, दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली के कार्यालय में खुद को पेश किया और खुद को निर्दोष बताया। विनोद गर्ग को 24 अगस्त, 2003 को फिर से पेश होने का निर्देश दिया गया, जब उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के तहत एक स्वैच्छिक बयान दिया, लेकिन उस दिन उनका बयान पूरा नहीं हो सका, इसलिए उन्हें फिर से तलब किया गया-25 अगस्त, 2003 के नोटिस के माध्यम से 25 अगस्त को ही पेश होने के लिए। 24 अगस्त, 2003 के अपने बयान में, विनोद गर्ग ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वह 7/3, रूप नगर, दिल्ली में एक और आवासीय परिसर का मालिक है। उक्त परिसर की तलाशी 25 अगस्त, 2003 को भी ली गई थी जब विनोद गर्ग ने फिर से एक 'स्वैच्छिक बयान' दिया जिसमें खुलासा किया गया था कि कैसे वह कुछ सीमा शुल्क अधिकारियों की कथित मिलीभुगत से ओवर इनवॉयसिंग आदि के माध्यम से डीईपीबी क्रेडिट अर्जित कर रहा था। इसके बाद, उन्हें 25 अगस्त,

2003 को गिरफ्तार किया गया और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष पेश करने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, उनके भाई नरसी दास गर्ग को 23 और 24 अगस्त, 2003 को डीआरआई, लुधियाना में पेश होने के लिए नोटिस भेजे गए, जो पेश हुए और उनके बयान भी दर्ज किए गए। यह भी खुलासा किया गया कि इसी तरह का एक तार प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा गया था, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 की आपराधिक विविध संख्या एम-3970 माना गया था, लेकिन इसे 4 नवंबर, 2003 को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने 25 अक्टूबर, 2005 के आदेश में निहित निर्देशों की मांग करते हुए इस न्यायालय से भौतिक तथ्यों को छुपाया।

(7) एकल न्यायाधीश ने 29 मई, 2006 के अपने आदेश में कहा कि डीआरआई के अधिकारियों को विधिवत सेवा प्रदान की गई थी; उन्हें इस न्यायालय में लंबित कार्यवाही के बारे में जानकारी थी; भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल ने मामले में उपस्थित होने के लिए पैनल में शामिल वकील को निर्देश दिया था और उनके कनिष्ठ उस समय उपस्थित थे जब 25 अक्टूबर, 2005 का आदेश पारित किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने डीआरआई, विशेष रूप से इसके संयुक्त निदेशक-धीरज रस्तोगी के आचरण की भी निंदा की और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे उन्होंने अपनी जेब से उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति को देने का निर्देश दिया। उपरोक्त बाद के आदेश ने दो संबंधित अपीलों को जन्म दिया है, जैसा कि पहले कहा गया है।

(8) इस बीच, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 (1) के तहत प्रतिवादी के पति विनोद गर्ग के खिलाफ 20 अक्टूबर, 2003 को एक निरोध आदेश पारित किया गया था। उस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था-दिनांक 4 अप्रैल, 2004 के आदेश द्वारा। प्रत्यर्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2004 की आपराधिक अपील संख्या 821 को प्राथमिकता दी और इसे 21 सितंबर, 2004 के निर्णय के माध्यम से यह देखने के बाद अनुमति दी गई कि चूंकि निरोध आदेश में उल्लिखित आधारों में से एक यह था कि प्रत्यर्थी के पति द्वारा आयातित सामग्री धातु स्क्रैप थी और मिश्र धातु इस्पात नहीं बल्कि रासायनिक विश्लेषण पर, यह पाया गया था कि नमूने केवल मिश्र धातु इस्पात से बने थे, इसलिए निरोध आदेश कानून में कायम नहीं रह सकता था।

(9) 2005 का आपराधिक विविध आवेदन संख्या 379 मामले के इस भौतिक पहलू पर मौन था।

(10) इस प्रकार, अभिलेख से पता चलता है कि डीआरआई अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी के पति की कथित अवैध हिरासत की जांच करने के लिए 25 अक्टूबर, 2005 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लुधियाना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए जाने से बहुत पहले, न केवल वह पहले ही इस तरह की हिरासत से रिहा हो चुका था, बल्कि उसके निवारक निरोध आदेश को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

(11) प्रतिवादी याचिकाकर्ता डीआरआई अधिकारियों द्वारा अपने पति की कथित 'अवैध हिरासत' की 'जांच' के लिए अभी भी क्यों उत्सुक थी, यह अब कोई रहस्य नहीं है। जैसा कि पहले देखा गया है, प्रतिवादी के पति, विनोद गर्ग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 23 और 24 अगस्त, 2003 को डीआरआई अधिकारियों के समक्ष दो आत्म-उत्तेजक प्रकटीकरण बयान दिए थे। निवारक निरोध आदेश को रद्द किए जाने के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि विनोद गर्ग और उनके भाई-नरसी दास गर्ग चालान मूल्य से अधिक पर वस्तुओं के निर्यात के खिलाफ सार्वजनिक पात्रता पास बुक योजना के तहत ऋण के कथित धोखाधड़ी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय XIII और XIV के तहत अर्ध-न्यायिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। चूंकि राजस्व द्वारा उनके खिलाफ साक्ष्य के एक भौतिक टुकड़े के रूप में आत्म-निंदात्मक बयानों पर भरोसा किए जाने की संभावना है, इसलिए विनोद गर्ग और उनका परिवार यह सुझाव देकर उनके साक्ष्य मूल्य को ध्वस्त करने के लिए बेताब है कि वे बयान स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे।

(12) हम यहां यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि इन अपीलों में नोटिस जारी करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 29 मई, 2006 के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांक 31 जनवरी, 2007 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लुधियाना द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट, जैसा कि लर्नड सिंगल जज द्वारा निर्देशित किया गया है, प्रस्तुत की जाए। इसके सम्मान में, उक्त जांच रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड में रखा गया

है और हमें बताया गया है कि एसएसपी, लुधियाना ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादी के पति को 23 से 25 अगस्त, 2003 के बीच डीआरआई के अधिकारियों द्वारा 'अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

(13) हमने अपीलार्थियों की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मोहन प्रसारन और प्रतिवादी याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री आर. एस. चीमा को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

हमारे विचार के लिए दो बुनियादी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला यह कि क्या इस न्यायालय को आपराधिक रिट याचिका पर विचार करने और निर्देश जारी करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त था और दूसरा, क्या इस तरह के निर्देश हेबियास्कॉर्पस की रिट की मांग करने वाली याचिका में जारी किए जा सकते थे, जब कथित बंदी को पहले ही रिहा कर दिया गया था और यहां तक कि बाद के निवारक निरोध आदेश को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था?

(15) यह न्यायालय निस्संदेह एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है यदि 'कार्रवाई का कारण' या इसका कोई हिस्सा इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले में अधिकारिता ग्रहण करने के लिए दो कारकों पर भरोसा किया है, अर्थात्, "(i) नरसी दास गर्ग को लुधियाना से उठाया गया है; और (ii) मधु गर्ग से तार भी लुधियाना से प्राप्त हुआ था। हमारे विचार में, ये दोनों कारक अप्रासंगिक हैं और वर्तमान मामले में कोई 'कार्रवाई का कारण' या उसका हिस्सा नहीं हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, नरसी दास गर्ग की कथित अवैध हिरासत के संबंध में, उनकी पत्नी-श्रीमती राकेश गर्ग ने एक अलग तार भेजा था जिसे 2003 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1032 माना गया था और इस अदालत ने 16 दिसंबर, 2003 को इसे निष्फल बताते हुए निपटाया था। जहाँ तक प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय को भेजे गए तार का संबंध है, वह किसी भी तरह से 'कार्रवाई के कारण' का हिस्सा नहीं है, जो अब तक एक अच्छी तरह से परिभाषित अर्थ है। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पिन लिमिटेड बनाम हैरिबॉक्स स्वालराम (1) में उनके सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप्स ने कहा कि केवल यह तथ्य कि रिट याचिकाकर्ता कलकत्ता में व्यवसाय करता है या उसके द्वारा किए गए पत्राचार का जवाब कलकत्ता में प्राप्त हुआ था, कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग नहीं है और इसलिए,

कलकत्ता उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(16) कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, उच्च न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या 'कार्रवाई के कारण' के समर्थन में प्रस्तुत किए गए अभिन्न तथ्य एक कारण का गठन करते हैं ताकि उसे विवाद का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाया जा सके और यह कि इस तरह के कारण का पूरा या हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

भारत संघ और अन्य बनाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को 'कार्रवाई के कारण' के समर्थन में अनुरोध किए गए सभी तथ्यों से संतुष्ट होना चाहिए कि ये तथ्य एक कारण का गठन करते हैं ताकि अदालत को उस विवाद का निर्णय करने का अधिकार दिया जा सके जो कम से कम उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर आंशिक रूप से उत्पन्न हो रहा है। पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक तथ्य वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि वे तथ्य न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर 'कार्रवाई के कारण' को जन्म देते हैं, जब तक कि वे तथ्य ऐसे न हों जिनका मामले में शामिल मामले के साथ संबंध या प्रासंगिकता हो।

(18) वर्तमान मामले में, माना जाता है कि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता का पति अपने दिल्ली आवास पर था जब उसे डीआरआई अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अवैध हिरासत में ले लिया गया था। हिरासत में रहते हुए, विनोद गर्ग को कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया और उन्हें केवल दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसी तरह, डीआरआई द्वारा विनोद गर्ग को कथित नोटिस भेजे गए और उन्हें उनके दिल्ली के पते पर भेजा गया। उनके आत्म-निंदात्मक बयान भी केवल दिल्ली में दर्ज किए गए थे। इस प्रकार, विनोद गर्ग की कथित "अवैध हिरासत" से संबंधित सभी घटनाएं केवल दिल्ली में शुरू हुईं और समाप्त हुईं। जबकि प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता कथित बंदी की पत्नी थी, उसके पास 'कार्रवाई का अधिकार' था, लेकिन इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उसे कोई 'कार्रवाई का कारण' नहीं दिया गया था।

(19) यह मानते हुए कि यह एक ऐसा मामला था जहां यह न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते थे, फिर भी प्रतिवादी किसी भी मंच का चयन कर सकता था। उन्होंने दोनों उच्च न्यायालयों को तार भेजने का विकल्प चुना, जिन्हें आपराधिक विविध याचिकाओं के रूप में माना जाता था। दिल्ली उच्च न्यायालय में उसकी याचिका को 4 नवंबर, 2003 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, उससे कम से कम 2005 की आपराधिक विविध संख्या 379 को स्थानांतरित करते समय इस न्यायालय में इस तथ्य का खुलासा करने की उम्मीद थी।

हालाँकि, हम इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि यह न्यायालय रिट याचिका पर विचार कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उचित निर्देश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट का उपयोग किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष सबसे अधिक बार लाने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्ष को कैद या हिरासत में रखना अवैध नहीं है। इस प्रकार, इसका तात्पर्य है कि जब अवैध निरोध की शिकायत होती है, तो उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के माध्यम से बंदी के व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए सुरक्षित कर सकता है कि उसे वैध हिरासत में रखा गया है या नहीं। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का पति उस समय अभिरक्षा में नहीं था जब याचिका 25 अक्टूबर, 2005 को निपटारे के लिए आई थी और इसे एक तरह से निष्फल कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में, उपयुक्त मार्ग यह हो सकता था कि कथित बंदी या रिट याचिकाकर्ता को एक उपयुक्त मंच के समक्ष "मुआवजा" या किसी अन्य घोषणात्मक राहत जैसे उपाय की मांग करने की स्वतंत्रता दी जा सकती थी ताकि किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह न हो।

(21) मामले के अभिलेख से पता चलता है कि अपीलार्थियों को ठीक से पेश नहीं किया गया था और अधिकारियों और उनके वकील के बीच संवाद की वास्तविक कमी की उनकी याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा हल्के में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

(22) ऊपर बताए गए कारणों से, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक निष्फल मामले में जाँच के लिए निर्देश जारी किए। तदनुसार हमने 25 अक्टूबर, 2005 के आदेश को उस हद तक दरकिनार कर दिया। इसके उत्तर-क्रम के रूप में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 29 मई, 2006 के बाद के आदेश को अनिवार्य रूप से हटा दिया जाना चाहिए और उसे भी दरकिनार कर दिया जाता है। इसका मतलब यह होगा कि

लुधियाना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का कोई कानूनी मूल्य या प्रभाव नहीं है।

(23) हालाँकि, ऊपर की गई टिप्पणियों या हमारे द्वारा किए गए निष्कर्षों को इस प्रश्न पर निर्णय के रूप में नहीं लिया जाएगा कि क्या प्रतिवादी का पति 23 से 25 अगस्त, 2003 तक डीआरआई अधिकारियों की अवैध हिरासत में था। हम प्रतिवादी के लिए उचित कार्यवाही में यह साबित करने के लिए खुला छोड़ते हैं कि विनोद गर्ग को वास्तव में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था या अवैध हिरासत की उस अवधि के दौरान उनसे आत्म-निंदात्मक बयान निकाले गए थे। इसी प्रकार, अपीलार्थी या तो उक्त अवधि के दौरान विनोद गर्ग की कथित नजरबंदी को उचित ठहराने के हकदार होंगे या यह साबित करने के हकदार होंगे कि उन्हें उनके द्वारा कभी हिरासत में नहीं लिया गया था और उन्हें पहली बार 25 अगस्त, 2003 को ही गिरफ्तार किया गया था।

(24) हालाँकि, अपीलों का तदनुसार निपटान किया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा